

took place in the Connaught Circus, New Delhi branch of the bank in which two overdrafts were sanctioned against security of 'Kisan Vikas Patras' which were subsequently found to be fake. The CBI have registered a case on 27.8.1998 against three persons involved in the fraud in which loans were availed against 'Kisan Vikas Patras' which were later found to be out of a lot of 'Kisan Vikas Patras' found missing from a railway parcel during transit from Nasik Press to Calcutta. Some arrests have been made. The bank has called for the explanation of the concerned staff and has also issued notices to all its branches/controlling authorities to exercise caution while financing against security of 'Kisan Vikas Patras'.

"इंडियन बैंक्स एमर्ग टैन मोस्ट करए" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2519. श्री बरजिंदर सिंह:

श्री बलवन्त सिंह राम्वालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 नवम्बर, 1998 के "दि बिजनेस स्टैंडर्ड" समाचार-पत्र में "इंडियन बैंक्स एमर्ग टैन मोस्ट करए: मौदीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने भारतीय बैंकों के संबंध में अपनी रण्य प्रकट की है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बर एम.आर. जनार्दनन):

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) यह समाचार म्यूचुअल इन्वेस्टर सर्विस द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर, 1998 को एक सम्मेलन में दिए गए "इन्फोर्मिंग ट्रांसपैरेंसी इन एशियन बैंकिंग सिस्टम" नामक पत्र पर आधारित है। इस पत्र में घटिया पारदर्शिता की भूमिका पर पूर्ण एशियाई वित्तीय संकट पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण किया गया है। पत्र में

बताया गया है कि चूंकि पारदर्शिता की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है तथा इसकी अवधारणा स्वयं में ही कुछ कुछ विषयपरक रहती है, इसलिए पारदर्शिता के मात्रात्मक उपाय तैयार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सर्वेक्षण के परिणाम पर एजेंसी द्वारा भरोसा दिलाया गया है जिसमें कई देशों में भ्रष्टाचार की ज्ञात स्तर की मात्रा बताने का प्रयास किया गया है। ये सर्वेक्षण गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया गया है। प्रत्येक देश की 1 से 10 तक रैंकिंग केवल सर्वेक्षणों में भाग लेने वाले व्यावसायियों की उपलब्धि के आधार पर ही की गई है। किसी देश को तभी भ्रष्टाचार सूची में शामिल किया जा सकता है जब कम से कम चार करक हों। एजेंसी के अनुसार, कथित रूप से यह सूची, विभिन्न देशों की बैंकिंग प्रणाली की पारदर्शिता का उपाय है। पत्र में उल्लिखित एशियाई बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता सुधार में कई एशियाई देशों समेत कुछ और देशों को भी संदर्भित किया गया है। परन्तु इसमें न तो विशेष रूप से भारत का उल्लेख किया गया है और न ही भारतीय बैंकों का। भारत का उल्लेख केवल परिशिष्ट में है जिसमें 52 देशों की सूची है और उन देशों में ज्ञात भ्रष्टाचार के स्तर को दर्शाता है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार, बैंकों के लेखों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सतत आधार पर कार्रवाई करते रहे हैं। परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में कई उपाय किए गए हैं जिससे बैंकों के प्रकटीकरण में पहली की अपेक्षा वृद्धि हुई है। आय की पहचान और आस्ति वर्गीकरण के लिए उद्देश्यपरक मानदण्डों के दृढ़ता से लागू किए जाने के कारण बैंकों के परिचालनों और लेखों में अधिक पारदर्शिता आई है।

आर्थिक स्थिति पर विचार करने हेतु परिषदों का गठन किया जाना

2520. श्री राज भोहिन्दर सिंह:

श्री बलवन्त सिंह राम्वालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विगत माहों के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर विचार करने एवं इस संबंध में सुझाव देने के लिए दो परिषदों का गठन किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दोनों परिषदों को अलग-अलग दायित्व भी सौंपे गये थे;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन परिषदों ने अब तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) से (घ) 27 अगस्त, 1998 और 28 अगस्त, 1998 को सरकार ने प्रधानमंत्री की "आर्थिक सलाहकार परिषद्" और "व्यापार तथा उद्योग परिषद्" नामक दो परिषदों का गठन किया जिनकी संरचना निम्नलिखित है:

आर्थिक सलाहकार परिषद्

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री

सदस्य: डा० आई.जी. पटेल

प्रो० पी.एन. धर

डा० मंटिक सिंह आहलुवालिया

डा० अर्जुन सेनगुप्ता

डा० किरिट पारिख

डा० अमरेश बागची

डा० अशोक देसाई

श्री जी.वी. रामकृष्ण प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव

सदस्य सचिव: प्रधानमंत्री के सचिव

व्यापार और उद्योग परिषद्

अध्यक्ष: प्रधान मंत्री

सदस्य: श्री रतन टाटा

श्री मुकेश अम्बानी

श्री आर.पी. गोयनका

श्री पी.के. मित्तल

श्री कुमार मंगलम बिड़ला

श्री सुरेश कृष्णा

(टी.वी.एस. समूह)

श्री एन.आर. नारायणमूर्ति

(सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ)

श्री नुस्ली वाडिया

श्री एस. मुत्तैया

डा० परविन्दर सिंह

(उत्तर भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधि)

प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव

सदस्य सचिव: प्रधान मंत्री के सचिव

आर्थिक सलाहकार परिषद् प्रधानमंत्री और परिषद् के सदस्यों के बीच अतिमहत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत विचार-विमर्श के लिए एक अवसर प्रदान करेगी। इसी प्रकार, व्यापार और उद्योग परिषद् प्रधानमंत्री और व्यापार तथा उद्योग परिषद् के सदस्यों के बीच व्यापार और उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत

विचार-विमर्श के लिए एक अवसर प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग संबंधी सलाहकार परिषद् के तहत छह विशेष विषय संबंधी समूह गठित किए गए हैं। इन विशेष विषय संबंधी समूहों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं जिन पर आगे की कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर एवं आजमगढ़ जनपदों में बैंकों की शाखाएँ

2521. श्री मुनव्वर हसन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर एवं आजमगढ़ जनपदों में कार्यरत विभिन्न बैंकों की शाखाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान दोनों जनपदों में किन-किन बैंकों की शाखाएँ खोली जाएंगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा भेजे गए अनुसार, 30 सितम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ जिलों में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का बैंक-वार विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ जिलों में शाखाएँ खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निम्नलिखित प्राधिकार-पत्र जारी किए हैं:—

जिला	बैंक	केन्द्र
मुजफ्फरनगर	यूनियन बैंक आफ मुजफ्फरनगर इंडिया	
मुजफ्फरनगर	ओरियंटल बैंक आफ मिरापुर कामर्स	
मुजफ्फरनगर	ओरियंटल बैंक आफ कैरना कामर्स	
मुजफ्फरनगर	पंजाब नेशनल बैंक	सदर बजार, मुजफ्फरनगर
आजमगढ़	कैरना बैंक	आजमगढ़
आजमगढ़	बैंक आफ इंडिया	आजमगढ़

आधारभूत सुविधाओं आदि के लिए व्यवस्थाओं के होने के पश्चात ही शाखाएँ खोली जाती हैं।